



WWJMRD 2018; 4(3): 218-221
www.wwjmr.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
UGC Approved Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
E-ISSN: 2454-6615

कुलदीप वर्मा

(शोध-छात्र)

रक्षा एवं स्ट्रेतेजिक अध्ययन
विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद भारत

भारत-नेपाल सम्बन्ध एवं वर्तमान स्थिति

कुलदीप वर्मा

संक्षेपिका

भारत-नेपाल विवाद मुख्य रूप से व्यापार और पारगमन सन्धियों को लेकर प्रारम्भ हुआ। यह सही है कि दोनों देशों के बीच अक्टूबर, 1988 में व्यापार सन्धि पर प्रारम्भिक हस्ताक्षर हो गये थे। भारत को यह आशा थी कि भारतीय सामानों पर नेपाल द्वारा लगाया गया भारी सीमा शुल्क स्वतः समाप्त हो जायेगा। परन्तु ऐसा नहीं किया जा सका। दूसरी ओर नेपाल ने सड़क से आने वाले चीन के माल पर साठ प्रतिशत की छूट दे दी। अतः प्राथमिकता का वादा करके भारत के साथ वादा खिलाफी की गई। इसके अतिरिक्त भारत व्यापार और पारगमन दोनों के लिए संधि चाहता है जबकि नेपाल अलग-अलग संधि चाहता है।

शब्दार्थ: नेपाल, चीन, भारत, लोकतंत्र, मैत्री, तस्करी, मधेस,

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक भाग है तथा यह स्थलों से घिरा हुआ देश है। भारत की लगभग 1860 किमी० सीमा नेपाल से सटी है। यह भारत एवं चीन के बीच स्थित है। हिमालय की गोद में बसे नेपाल की उत्तरी सीमा तिब्बत से मिलती है तथा इसकी पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमायें भारत से मिलती हैं। नेपाल दोनों तरफ विशाल देशों से भूबद्ध ;रन्दकसवबाद्ध है। इसका क्षेत्रफल 1,48,000 किमी² के लगभग है। इसकी जनसंख्या 3 करोड़ के लगभग है।

सन् 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने काठमाण्डू पर फतह कर एकीकृत साम्राज्य की नींव डाली। सन् 1846 में नेपाल पर राजाओं का वर्चस्व हो गया, जिन्होंने सम्राट को शक्तिहीन कर नेपाल को विश्व से काट दिया। बाद में राजा और राणाओं के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यह तय हुआ कि राजा को 'पांच सरकार' तथा राजा को 'तीन सरकार' कहा गया।

1950 के उपरान्त की स्थिति

सन् 1951 में राजा, नेपाली कांग्रेस के बीच समझौता हुआ तथा प्रथम बार संसद हेतु चुनाव हुए तथा नेपाली कांग्रेस के वी०पी० कोइराला के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्षरत नेपाली कांग्रेस के प्रायः वरिष्ठ नेताओं की शिक्षा-दीक्षा भारत में हुई। इन नेताओं ने अपने देश में निरंकुश राजाशाही का अन्त कराया। 30 जुलाई 1950 को भारत में नेपाल के मध्य "भारत-नेपाल शान्ति व सहयोग" की एक सन्धि की। न तो 1947 से पूर्व और न ही इसके बाद बिट्रेन अथवा भारत ने नेपाल के आन्तरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप किया। भारत के प्रयास से नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 1956 में भारत के राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने नेपाल की यात्रा की।

1960 में नेपाल ने चीन के साथ "मित्रता एवं सहयोग" की सन्धि कर ली। फलतः 1961 में भारत एवं नेपाल के सम्बन्धों में कुछ दरार देखी गयी। 1962 में भारत-चीन युद्ध के समय नेपाल के साथ भारत के सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत-नेपाल सम्बन्धों में सुधार लाने का प्रयास किया। तथा 1965 में नेपाल नरेश ने भी भारत की यात्रा की इससे दोनों देश के बीच भ्रान्तियाँ दूर हुयी। श्रीमती इन्दिरा गाँधी के युग में दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को और मजबूत किया जा सका तथा नेपाल यह अनुभव करने लगा कि भारत की कोई साम्राज्यवादी आकांक्षाएँ नहीं हैं। उसे भारत की प्रभुसत्ता का आदर करना ही चाहिए। 13 अगस्त, 1971 को दोनों देशों के बीच एक पंचवर्षीय समझौता किया गया जिसके तहत भारत ने नेपाल के कच्चे माल के व्यापार की खुली छूट दे दी एवं उसे मार्ग सुविधायें भी प्रदान कर दी। नेपाल ने बांग्लादेश के अस्तित्व में आने

Correspondence:

कुलदीप वर्मा

(शोध-छात्र)

रक्षा एवं स्ट्रेतेजिक अध्ययन
विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद भारत

पर उसे तत्काल मान्यता प्रदान कर दी परन्तु 1975 में सिविकम के विलय के समय नेपाल नरेश वीरेन्द्र ने इसे विस्तारवादी कह डाला। उस समय इंदिरा गाँधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि नेपाल को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि भारत की मैत्री सदैव बरकरार रहेगी तथा यह मैत्रीएकतरफ से नहीं चल सकती।

सन् 1977 में जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने पर दोनों के बीच आपसी सम्बन्धों को और अधिक मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया, परन्तु कोईराला की गिरफ्तारी एवं उन्हें मृत्युदण्ड दिये जाने की घोषणा ने दोनों देशों के सम्बन्धों में दरार पैदा कर दी। सन् 1980 में इंदिरा गाँधी की सरकार के पुनः सत्तारूढ़ होने पर भारत-नेपाल सम्बन्धों में सुधार एवं सहयोग देखा गया। सन् 1987 में दोनों देशों के बीच 'व्यापार एवं पारगमन' की सन्धि की गई, जिसका नवीनीकरण राजीव गाँधी सरकार ने नहीं किया। नेपाल में लम्बे आंदोलन के बाद सन् 1990 में सम्राट वीरेन्द्र ने लोकतंत्र बहाल कर दिया। सन् 1991 के चुनाव में नेपाली काँग्रेस को बहुमत मिला। इसके बाद कई सरकारें बनीं तथा बर्खास्त हुईं।

भारत ने नेपाल की पंचवर्षीय योजनाओं में भरपूर सहायता दी है तथा उसकी आर्थिक दशा को सुधारने हेतु भी उदारता से ऋण दिया है। भारत नेपाल को कोलकाता बंदरगाह को उपयोग में लाने हेतु अनुमति प्रदान की गई। कोसी तथा त्रिशूली परियोजनाओं में भारत ने उदारता से अपार धनराशि खर्च की भारत ने अनेक सड़कों का निर्माण किया। भारतने नेपाल को 300 करोड़ रुपये से भी अधिक की सहायता दी तथा उसने नेपाल की बड़ी-बड़ी नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई एवं बिजली पैदा करने वाली अनेक परियोजनाओं को पूरा करके उसे तथा स्वयं को लाभान्वित किया है।

नेपाल जलीय संसाधनों में एक धनी देश है। यदि दोनों देश इस क्षेत्र में निकटतम सहयोग करें तो इससे न केवल नेपाल का कायापलट हो सकता है अपितु भारत की अतृप्ति ऊर्जा अर्थव्यवस्था को भी सम्बल प्राप्त हो सकता है। दोनों देश आज तक सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण तथा इसी प्रकार के आपसी लाभप्रद आर्थिक परियोजनाओं से वंचित रहे हैं। नेपाल में कृषि उत्पादन, सीमेंट और ऊर्जा के उत्पादन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारत-नेपाल विवाद

भारत-नेपाल विवाद मुख्य रूप से व्यापार और पारगमन सन्धियों को लेकर प्रारम्भ हुआ। यह सही है कि दोनों देशों के बीच अक्टूबर, 1988 में व्यापार सन्धि पर प्रारम्भिक हस्ताक्षर हो गये थे। भारत को यह आशा थी कि भारतीय सामानों पर नेपाल द्वारा लगाया गया भारी सीमा शुल्क स्वतः समाप्त हो जायेगा। परन्तु ऐसा नहीं किया जा सका। दूसरी ओर नेपाल ने सड़क से आने वाले चीन के माल पर साठ प्रतिशत की छूट दे दी। अतः प्राथमिकता का वादा करके भारत के साथ वादा खिलाफी की गई। इसके अतिरिक्त भारत व्यापार और पारगमन दोनों के लिए संधि चाहता है जबकि नेपाल अलग-अलग संधि चाहता है।

नेपाल ने अप्रैल, 1987 में आंशिक तौर से तथा सितम्बर, 1988 से पूरे देश में भारतीय मूल के लोगों के लिए रोजगार परमिट अनिवार्य कर दिया जबकि भारत ने 1950 की सन्धि का अनुपालन करते हुए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया। भारत में लगभग 35 लाख नेपाली रहते हैं। तथा नेपाल में 50,000 भारतीय रहते हैं। सन् 1950 की सन्धि के ही कारण अन्य विदेशी नागरिकों की भाँति उनका पंजीकरण नहीं किया गया है। यह सर्वविदित है कि भारत-नेपाल व्यापार का सबसे भयावह पहलू रहा है तस्करी। उनहहसपदहद्ध । भारत द्वारा दी गई तमाम सुविधाओं के बदले नेपाल ने भारत को और भारतीयों को तस्करी ही दिया। तस्करी नेपाल के सहयोग से फलफूल रही,

जिसके कारण भारत को सर्वाधिक हानि हुई। अतः भारत को नेपाल के मामले में फूँक-फूँक कर कदम उठाना होगा।

नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने फरवरी, 1996 में भारत की यात्रा की। उनकी राय में भारत की जनता और नेपाल की जनता के बीच बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं और ये निरन्तर अच्छे हो रहे हैं। उनकी इसी यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी के पानी और उस पर स्थापित पन बिजली परियोजना से तैयार बिजली के बंटवारे पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। इसके तहत 2,000 मेगावाट क्षमता की विशाल बिजली परियोजना पूरा करने का समझौता हुआ। इसके अनुसार नेपाल को लगभग 5 किलोवाट बिजली और 150 क्यूसेक पानी निःशुल्क प्रदान करेगा।

वर्तमान स्थिति

2014 में प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया। इसके उपरान्त प्रधानमंत्री की पिछले साल अगस्त की नेपाल यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक थी। यह 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम नेपाल यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालने के तीन महीनों से भी कम अर्से में यह यात्रा की। इस यात्रा से पहले भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हुई। जब इसकी अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने की। श्री नरेन्द्र मोदी अकेले-एकेले विदेशी हैं, जिन्हें नेपाल की संविधान सभा और संसद को संबोधित करने का सौभाग्य प्रदान किया गया।

नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को जब भूकंप आया तो वहाँ के प्रधानमंत्री थाइलैण्ड में थे, अपने देश में आई इस भीषण विपदा की जानकारी का पहला स्रोत उनके लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल की सहायता की घोषणा की। इस ऑपरेशन को "आपरेशन मैत्री" नाम दिया गया। भारत ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए भी भारी आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

नेपाल का संवैधानिक संकट व मधेशी समस्या

नेपाल पिछले कई दशक से अस्थिर और उपद्रवग्रस्त रहा है। शायद इसी कारण उसके 'संवैधानिक संकट' को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। नेपाल के लिए राजनैतिक अस्थिरता, असमंजस, संवैधानिक संकट या जनाक्रोश का हिंसक विस्फोट अपरिचित नहीं। राजपरिवार की नृसंस हत्या के पहले भी यह देश गृहयुद्ध की चपेट में था और माओवादी उत्पाद के कारण पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी। पड़ोसी भूटान के साथ रिश्ते तनावग्रस्त रहे हैं। और भारत के प्रति वैमनस्य, मतभेद, क्लेश और रोष का इतिहास काफी लम्बा है।

यह आशा स्वाभाविक थी कि नया संविधान अपनाते के साथ ही सारे राजनैतिक विवाद समाप्त हो जायेंगे और बुरी तरह विभाजित नेपाली शांति और विकास की दशा में गतिशील होने लगेगा। पर हुआ इसके विपरीत इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस नेपाली नेता मौकापरस्ती और असफलता का ठीकरा भारत के सर पर फोड़ने को व्याकुल है।

अनेक 'देशप्रेमी' नेपाली यह आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार ने नेपाल पर अंकुश लगाने के लिए ही तराई में सरहद पर नाकाबंदी की है। इसका खामियाजा नेपाल की निरीह जनता को भुगतान पड़ रहा है आदि। सोचने की बात यह है कि महीनों से जिस अराजकता का माहौल पूरे मधेस में व्याप्त है उसके लिए क्या पीढ़ी दर पीढ़ी काठमांडू में राज कर पहाड़ी नेता जिम्मेदार नहीं? क्या यह सच नहीं कि जिस संघीय प्रणाली का सपना नेपाल के नागरिकों को दिखलाया गया था वह इस संविधान में चकनाचूर हो चुका है? सबसे विचित्र बात हो यह है कि संविधान निर्मात्री सभा के 80 प्रतिशत सदस्यों ने इस संविधान का मसौदा पारित किया है। यह सुझाना कि भारत की शरारत से यह संकट पैदा हुआ था सरासर नाजायज है।

यहाँ तत्काल यह जोड़ने की जरूरत है कि यह सारा घटनाक्रम नेपाल का आंतरिक मामला है जिसमें भारत का नाम मात्र का हस्तक्षेप भी संगत नहीं पर यह सोचना कि भारत नेपाल की हिंसक उथल-पुथल को जो उसके अपने राष्ट्रहित के लिए गंभीर जोखिम बन रही है अनदेखा कर तटस्थ बैठा रहेगा तर्कसंगत नहीं।

सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल की अधिकांश जनता भारत के अधिक समीप है और मंगोल मूल के जनजातीय भी पूर्वोत्तर निवासियों के सम्बन्धी नजर आते हैं। सदियों से साझे की संस्कृति को राष्ट्रीय सम्प्रभुता के अहंकार में टुकड़ाने की भूल नेपाली नेता कर सकते हैं, नेपाली जनता नहीं। भारत खुद अनेक प्रकार की कठिन चुनौतियों से जूझ रहा है तब भी करोड़ों की संख्या में नेपाली नागरिक भारत में उन सुविधाओं को भोगते हैं जो सामान्यतः देश के नागरिकों तक सीमित रहती है।

असलियत यह है कि पिछले दशकों में भारत नहीं पश्चिमी देश अमेरिका, यूरोपीय समुदाय की परोपकारी संस्थाएँ संगठन, सरकारी तथा गैर-सरकारी, जापान, चीन के साथ सक्रिय रहे हैं। इनसे प्राप्त सहायता अनुदान से नेपाल के श्रेष्ठवर्ग में यह धारणा बलवान हुई है कि भारत की कोई खास जरूरत उन्हें नहीं रह गई।

मधेस में जिस 'बंध' का आयोजन संविधान से क्रुद्ध नेपाली नागरिकों ने किया था पर प्रचार यह किया गया कि यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ब्लॉकड था। हकीकत यह थी कि उग्र हिंसा पर उतारू भीड़ के तेवर देख भारतीय व्यापारी और वाहन चालको ने अपनी जान और माल को जोखिम में नहीं डाला। अक्सर हमारे छोटे पड़ोसियों को यह शिकायत रहती है कि उनके प्रति भारत का रवैया दादागिरी सरीखा रहता है यानी धौंस धमकी वाला। वर्तमान प्रसंग में यह शिकायत बिल्कुल बेबुनियाद है। जब तक संविधान निर्माण की प्रक्रिया जारी थी भारत ने यह लोभ संवरण किया कि नेपाल को कोई भी सलाह दे। कड़वा सच यह है कि नेपाल के निर्वाचित नेताओं में भविष्य के बारे में गहरा मतभेद है। भारत से किसी भी समझौते सौदे पर मनचाही रियायत हासिल करने के लिए चीनी तुरप चाल चलने की मनोवृत्ति भी नई नहीं। नेपाल की प्रमुख राजनीतिक दल के नेताओं ने शिकायत की कि तराई की नाकाबंदी भारत की साजिश है जो संविधान को अपनी इच्छानुसार संशोधित करवाना चाहता है।

मोदी सरकार को इस बात का पूराहसास है कि हमें जो कुछ भी नेपाल से चाहिए उसकी तुलना में नेपाल को भारत से कहीं अधिक चाहिए।

नेपाल की सरकार ने आरोप लगाया था कि भारत द्वारा नाकाबंदी के कारण उसे घनघोर तेल संकट का सामना करना पड़ा था भारत का रवैया 'सहानुभूतिपूर्ण' न होने के कारण मजबूर होकर उसे तेल की आपूर्ति के लिए चीन के साथ एमझौता करने की धमकी दी थी। चीन ने इस स्थिति का लाभ उठाकर यह पेशकश किया कि वह एक खरब डॉलर कीमत का तेल निःशुल्क सुलभ करायेगा और भविष्य में नेपाल की तेल-गैस की जरूरतें पूरा करने के लिए सहायता करता रहेगा। अब तक भारत के जरिये ही नेपाल तेल खरीदता रहा है। निश्चय ही चीन का इस क्षेत्र में प्रवेश भारत के हित में नहीं समझा जा सकता। इसे भारतीय राजनय की असफलता ही समझा जाना चाहिए।

नेपाल की संविधान निर्मात्री सभा से नेपाल के तराई वाले इलाके के निवासियों को जो आशा थी उसके धूल-धूसरित होने से ही यह संकट उपजा है। जिस बंद के कारण राजधानी काठमांडू में 'ऊर्जा संकट' विस्फोटक बना है उसका आयोजन संचालन मधेशी नेपालियों ने ही किया था। दिक्कत यह थी कि भारत ने इन आंदोलनकारियों के प्रति अपनी सहानुभूति मुखर करने में उतावली दिखलाई जिससे नेपाल में भारत विरोधियों को यह

कहने का मौका मिला कि भारत संविधान निर्माण के बारे में नेपाल को राय देने वाला कौन होता है?

काठमांडू से भारतीय विमान अपहरण तथा पाकिस्तान से प्रायोजित दहशगतगर्दों के शरण के सिलसिले में भारत की शिकायतें नाजायज नहीं। जाली भारतीय मुद्रा की तस्कारी भी नेपाल से होती रही है। रही बात सरहद पर हड़ताल-धरने या बंद की, सो यह उपद्रव भारत के हित में कदापि नहीं था। इस व्यापार से सिर्फ नेपाली ही नहीं भारतीय व्यापारी भी मालामाल होते रहे हैं। यह कहना कि क्यों भारत इस रूकावट को नहीं हटाता गैर जिम्मेदाराना बयान है क्योंकि यदि भारत के सैनिक दल शांति बरकरार रखने के लिए कुछ भी करते हैं तो यह आरोप प्रमाणित हो जायेगा कि भारत सरकार हस्तक्षेपकारी है। दिसम्बर, 2015 में नेपाल में भारत के राजदूत राकेश सूद ने स्वीकार किया कि भारत व नेपाल के सम्बन्धों में एक हल्की सी तल्खी आयी है। भारतीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी भारत व नेपाल सम्बन्धों को 'रोटी व बेंटी का सम्बन्ध' बताया और सभी प्रकार की असहमतियों को जल्द सुलझाने पर बल दिया।

फरवरी, 2016 में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री 0 के 0 पी 0 शर्मा ओली भारत की यात्रा पर आये तथा उन्होंने घोषणा कि नेपाल ने मधेसी लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए पहला संविधान संशोधन किया। उनकी इस यात्रा में दोनों देशों में परिवहन, व्यापार, जल ऊर्जा सहित कुल 9 प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पुनः दोनों राष्ट्रों के सम्बन्ध सामान्य होने की ओर अग्रसर हुए।

अभी हाल में ही हुए आम चुनाव में नेपाल में कम्युनिष्ट दलों ने बहुमत प्राप्त कर लिया है जो भविष्य में भारत के प्रति उनके कड़े रवैये के कारण आपसी सम्बन्धों में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है और के 0 पी 0 शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओस्टि सेन्टर) व लेनिनवादी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी ने मिलकर सात में से छः प्रान्तों में भी जीत दर्ज की है। इस जीत में एक सकारात्मक बात यह है कि वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता की समस्या से नेपाल को निजात मिलेगी और एक स्थायी सरकार का गठन हुआ है मधेशियों के समर्थन के उपरान्त भी नेपाली कांग्रेस जीत दर्ज करने में असमर्थ रही।

चीन लगातार नेपाल को 'श्रीलंका' की तरह कर्ज के जाल में फंसाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास जारी रखा है। वर्तमान सरकार के समक्ष आन्तरिक सौहार्द को बनाये रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। प्रचंड व ओली दोनो महत्वाकांक्षी नेता है, दोनों का आपसी सामंजस्य भी आवश्यक है नवम्बर, 2017 में नयी सरकार ने चीनी कम्पनी के बुदि गन्डकी नदी पर प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना ठेके को रद्द किया है।

जो भारत के लिए शुभ संकेत है। वर्तमान में नेपाल भारत व चीन दोनों से अपने -स्त्रातेजिक उपस्थिति का लाभ आर्थिक निवेश के रूप में उठा रहा है। जिससे भारत को सावधान रहना होगा। 15, फरवरी 2018 को नेपाल की नई सरकार पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री शहिद अब्बासी को प्रथम अतिथि के रूप में बुलाया जो भारत के लिए एक नया संकेत है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी नेपाल की यात्रा की और प्रधानमंत्री ओली ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को जनकपुर की यात्रा का निमंत्रण दिया है।

निष्कर्ष :- हकीकत यह है कि नेपाल की भौगोलिक विविधता तथा सामाजिक बहुलता भारत से कम नहीं आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन ने वर्ग संघर्ष के हिंसक विस्फोट की जमीन तैयार की है। दशकों चला गृहयुद्ध इसी कारण असरदार बना। रही बात चीन की तो चीन उस तरह नेपाल की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता जैसे भारत। तेल को ही लें, यह कल्पना

करना कठिन है हजारों किलोमीटर फैले दुर्गम बिब्वती पठार को पार कर सड़क मार्ग से लाखों मीट्रिक टन तेल नेपाल तक नियमित रूप से पहुँचाया जा सकता है।

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कुछ नेपाली नेताओं के मतों को हम दरकिनार कर वहाँ के लोगों की सोच को देखें तो भारत व नेपाल के सदियों पुराने सृदृढ़ सम्बन्ध अब भी अच्छे व गहरे हैं जो दोनों के हित में है तथा इसे भविष्य में और सहयोगात्मक बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जे0एम0 श्रीवास्तव : राष्ट्रीय सुरक्षा
2. बी0एल0 फाड़िया : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
3. 'भारत-नेपाल सम्बन्ध' : पुष्पेश पन्त न्यूज वर्ल्ड, पेज 1-4
4. 'नेपाल का आन्तरिक संकट और भारत'—दैनिक जागरण, 15 नवम्बर 2015
5. 'नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा'—हिन्दुस्तान 25 फरवारी 2016
6. 'भारत व उसके पड़ोसी देश की वर्तमान स्थिति'— वर्ल्ड फोकस, दिसम्बर 2015
7. वदेश मंत्रालय की रिपोर्ट (2015-16)
8. The Hindu
9. Ministry of External affairs report- 2016-17